

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**



Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक- /23 एल0ए0
सेवा में, 2856

दिनांक- 21-12-2024

उपवन संरक्षक
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क,
ज्योतिर्मठ

विषय- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन शैल्टर म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झूला पुल, ट्राली एवं हैली पैड निर्माण हेतु 0.893 हे. वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 1646/12-1 दिनांक 19.11.2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण मन्त्रालय एकीकृति क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/180/2016/एफ0सी0/1718 दिनांक 17.01.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में आख्या बिन्दुवार तैयार करते हुये इस कार्यालय के पत्रांक 1099/24 एल0ए0 दिनांक 06.07.2022 द्वारा पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है पुनः अनुपालन आख्या तैयार कर बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:-

बिन्दु सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्वीकृति वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण: (क) वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1786 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा। एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि/सी0ए0 Rate for 1-660 he area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लानटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। (ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्लू एल0एम0पी0 क्षेत्र को परियोजना के लिए कार्यअनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	उक्त परियोजना में 1 हे0 से कम वनभूमि प्रभावित होने की दशा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लागू नहीं है।

Bujl

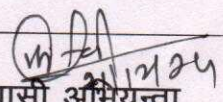
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि, आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन स्तंभन की लागत परयोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण और सीमांकन स्तम्भ लागत को वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य: (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 01.08.2003, 28.03.2008 24.08.2008 एवं 09.05.2006 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt) दिनांक 30.10.2023 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.893 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(एन०पी०वी० एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि रु. 1683711.00 (सोलह लाख तिरासी हजार सात सौ ग्यारह) एस०बी०आई०एन० 22186624777 दिनांक 05.07.2022 द्वारा आर०टी०जी०एस० के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। वनभूमि क शुद्ध वर्तमान दर में अतिरिक्त वृद्धि होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया लायेगा। संलग्न -2 न. (ख) वन भूमि के शुद्ध एन०पी०वी० वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हों जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो के राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 trees से अधिक नहीं हेगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों का न्यूनतम पातन किया जायेगा। प्रभावित होने वाले वृक्षों का न्यूनतम पातन कार्य वन विभाग के पक्ष की निगरानी में किया जायेगा।

Bug

7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड से स्थानांतरित जमा कर दिया गया है।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	निर्धारित शर्त का अनुपालन मान्य है। प्रमाण पत्र सलग्न है।
9	पर्यावरण (संरक्षक) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। शर्त मान्य है।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि में किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों कैरोसीन/वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था की जायेगी।
13	संबन्धित मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward backward bearing अंकित हो।	प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य के समय वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना हेतु उपयोग किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी	शर्त मान्य है।

Bu

	प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
18	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मान्य है।
19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविद्विष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किय जायेगा।	प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल हेतु चयनित स्थलों पर वन विभाग की निगरानी में मलवा निस्तारण किया जायेगा। अनावश्यक रूप से वन भूमि में मलवा निस्तारण नहीं किया जायेगा।
20	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल है। (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त मान्य है।


 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
 B. गोपेश्वर

पत्रांक - / 23 एल0ए0 तददिनांकित
 प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता (प्रथम) लो०नि०वि० गोपेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित की
 उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
 प्रतिलिपि:- खण्डीय अमीन लो०नि०वि० गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

अधिशासी/अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
 गोपेश्वर।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-07-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	19920905378
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/103/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	1683711/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Eighty-Three Thousand Seven Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508919920905378 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy
Email: cb0371@unionbankofindia.com



Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Chamoli

SBIN 5 22186624777

forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS2

05 JUL 2022

अधिसूचना
राष्ट्रीय खण्ड लो० नि० वि०
प्रतिपादित

प्रमाण पत्र ।

य-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घंघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन शेल्टर म्यूलहट गैंगहट शुलभ शौचालय वास आउट पैदल मार्ग झूला पुल ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण हेतु 0.893 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

प्रमाणित किया जाता है कि एन०पी०वी० देय धनराशि में किसी प्रकार से कोई वृद्धि होती है । तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढी हुई धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा ।

अधिशसी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०,
गोपेश्वर।

अधिशसी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०,
गोपेश्वर।

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

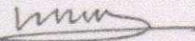
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.893 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Rain Shelter, Mule hut, Gang Hut, Sulabh Sochalaya, Bridle Suspension Bridge, Trolly, Halipad and Reconstruction of washout bridle road Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Joshimath Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.893 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature



(Vinod Kumar Suman)
 (District Magistrate Chamoli)

DM FRA Letter

अधिसासी अभियन्ता
 प्रालीय खण्ड लो० नि० वि०
 गोपेश्वर
 21/11/24

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 29.07.16 time 10.30 AM at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.893 hect for the construction of Rain Shelter, Mule hut, Gang hut, Sulabh Sochalaya, Bridle Suspension Bridge, Trolley, Halipad and Reconstruction of washout Bridle road Under PWD Gopeshwar Under State Sector at Joshimath Block in District- Chamoli, forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 29.07.16

[Signature]
21/12/16
अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Signature
[Signature]
29.07.16
(Vinod Kumar Suman)
District Magistrate, Chamoli
चमोली

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 हे. सिविल/आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 2-7-16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | | |
|---------|------------------|---------------------------|---------|
| 1- श्री | शैलेंद्र जेठा | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री | सुरेश कुमार दुबे | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री | विजय प्रसाद पुरि | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 4- श्री | शमशेर प्रसाद | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में उपस्थित करवाया गया। उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन शेल्टर म्यूलहट गैंगहट निर्माण हेतु 0.893 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जनजाति से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रस्ताव में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उप जिलाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सचिव
उप जिलाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सचिव
उप जिलाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सचिव

अधिशाली अभियन्ता
राष्ट्रीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

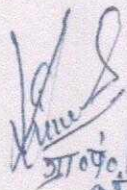
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

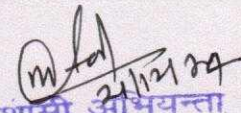
चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्रामपंच/वि० ११०
११/१२



DM FRA Letter


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोमुखर

